



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482
No. 482;

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 13, 1986/आश्विन 23, 1908
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 15, 1986/ASVINA 23, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 1150(अ):--भूमि अर्जन (कंपनी) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रावधान जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 55 की उपधारा (2) की अपेक्षासर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 4 सितंबर, 1985 के पृष्ठ 1 और 2 पर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 713(अ) तारीख 4 सितंबर, 1985 के अधीन प्रकाशित किया गया था और ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उत्तरे प्रस्तुत होने की संभावना थी, उक्त तारीख से प्रतिकी उक्त राजपत्र की, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गईं, वे.गो.स. नि. की अधि की सनाधि से पहले आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की, जिसमें पूर्वोक्त प्रावधान नियम प्रकाशित हुए थे, प्रतियां 10 सितंबर, 1985 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रावधान नियमों की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमि अर्जन (कंपनी) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

- (1) इन नियमों का नाम भूमि अर्जन (कंपनी) (संशोधन) नियम, 1936 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होंगे
- भूमि अर्जन (कंपनी) नियम, 1963 में;--
 - नियम 3 के उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(2) समिति में निम्नलिखित होंगे:--

 - सरकार के राजपत्र, कृषि और उद्योग विभागों के सचिव या उक्त विभागों में से प्रत्येक के ऐसे

अन्य अधिकारी जिन्हें समुचित सरकार नियुक्त करे,

(ii) अन्य ऐसे सदस्य, जिन्हें समुचित सरकार ऐसी अधि के लिए नियुक्त करे जो, आवेग द्वारा, विनिवृष्ट की जाए, और

(iii) विभाग का सचिव, या उसके द्वारा प्रातिनिधित्व कोई अधिकारी जो उन प्रयोजनों का व्यवहार करता हो जिनके लिए कम्पनी भूमि का अर्जन करने की प्रस्थापना करती है।”;

(ii) नियम 6 के उपविध (1) में, “अत्यावश्यकता की कितनी वया में, जहाँ किसी भूमि का कब्जा धारा 17 के अधिन लेने का प्रस्ताव किया जाता है” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“9. कम्पनी के संबंध में विशेष उपबन्ध :—

जब किसी कम्पनी द्वारा किसी भूमि के अर्जन के लिए कोई आवेदन समुचित सरकार को दिया जाता है, तब ऐसा अर्जन साधारणतया अधिनियम के भाग 7 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।”

[फा.सं. 12011/32/19/84-(एल आर डी)]
जे. सी. जेटली, प्रतिरिक्त सचिव

विषय: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 22-6-1963 के पृष्ठ 487 से 490 पर छात्र और कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1073, तारीख 22-6-1963 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 9th October, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1150(E).—Whereas the draft rules further to amend the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963 were published as required by sub-section (2) of section 55 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) at page 2 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th September, 1985, under the notification of the Ministry of Agriculture and Rural Development (Department of Rural Development) No. G.S.R. 713(E), dated the 4th September, 1985 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette in which the aforesaid draft rules were published were made available to the public on the 10th September, 1985;

And whereas the objections and suggestions received in respect of the said draft rules have been taken into consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 55 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Land Acquisition (Companies) (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963,—

(i) for sub-rule (2) of rule 3, the following shall be substituted, namely:—

“(2) The Committee shall consist of:—

(i) the Secretaries to the Government of the Departments of Revenue, Agriculture and Industries or such other officers of each of the said Departments as the appropriate Government may appoint.

(ii) such other members as the appropriate Government may appoint for such term as that Government may, by order, specify, and

(iii) the Secretary to the Department or any officer nominated by him dealing with the purposes for which the company proposes to acquire the land.”;

(ii) in sub-rule (1) of rule 6, the words, “in any case of urgency where possession of any land is proposed to be taken under section 17”, shall be omitted;

(iii) for rule 9, the following rule shall be substituted, namely :—

“9. Special provision in relation to a company—
When an application is made to the appropriate Government for acquisition of any land by a company, such acquisition shall ordinarily be made in accordance with the provisions of Part VII of the Act”.

[File No. 12011/32/19/84-(LRD)]

J. C. JETLI, Addl. Secy.

NOTE.—The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 22nd June, 1963 at pages 487 to 490 vide Government of India notification, in the Ministry of Food and Agriculture, Department of Agriculture, No. G.S.R. 1973 dated the 22nd June, 1963.